# बड़ी हिस्सेदारी बिक्री पर नजर बनी रहेगी

दीपम सचिव का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ समस्याएं आई हैं

मुंबई, 3 जुलाई

वेश एवं सार्वजनिक प्रबंधन (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं. लेकिन सरकार चाल वित्त वर्ष में अपने 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी हिस्सेदारी बिक्री पर ध्यान बरकरार रखेगी।

भारत बॉन्ड ईटीएफ पर एक वेबिनार में बोलते हुए पांडे ने कहा. 'कई रणनीतिक सौदे हो रहे हैं और वे सही दिशा में आगे बढ रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ समस्या आई थी।

सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से बड़े बिक्री सौदों के लिए आशय पत्रों (ईओआई) के



लिए समय-सीमा बढाई है।

हाल में सरकार ने एयर इंडिया के लिए सौंपी जाने वाली बोलियों के लिए अंतिम समय-सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की है। सरकार ने ईओआई सौंपने के लिए समय-

पर काम कर रही है

दी है। दीपम सचिव ने इस बारे में सवाल का जवाब देने में बचाव किया कि क्या सरकार मौजूदा बाजार हालात को देखते हए वित्त

सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर वर्ष 2021 के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य में बदलाव लाने पर विचार कर रही है।

विनिवेश पर एक नजर

■सरकार ने कोविड-19 की वजह से

बोलियां सौंपने की समय-सीमा

■एलआईसी आईपीओ से सरकार

**■**निवेश बैंकरों का कहना है कि

मिलने की संभावना है

को 90,000 करोड़ रुपये की रकम

विपरीत बाजार हालात ने विनिवेश

लक्ष्य की राह में चुनौती पैदा की है

इंडिया में बड़ी बिक्री की योजनाओं

■सरकार भारत पेट्रोलियम, एयर

बढ़ा दी थी

पांडे ने बीमा दिग्गज एलआईसी की आईपीओ प्रक्रिया के बारे में ताजा जानकारी देने से बीईएमएल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स ऐंड कम्प्रेशर शामिल हैं और सेल में भी कुछ हिस्सेदारी बेची जानी है।

बडी बिक्री में एयर इंडिया,

मई में सरकार ने कहा था कि रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम चार कंपनियां होंगी।

भारत बॉन्ड ईटीएफ की दुसरी सीरीज के जरिये. सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां 14,000 करोड़ रुपये जुटा सकेंगी।

अन्य सरकारी ईटीएफ (जिनमें निवेशक अलग अलग सरकारी पीएसय के इक्विटी शेयरों में निवेश कर सकते हैं) के विपरीत, भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेशकों को सरकारी पीएसयू के ऋण पत्रों के पोर्टफोलियो में निवेश की अनुमति होगी। ईटीएफ अभिदान के लिए 14 जुलाई को खुलेगा और 17 जलाई को बंद होगा।

# भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण शुरू

पहला चरण पिछले दिसंबर में शुरू हुआ था और तब 12,400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे

अनुप रॉय मुंबई, 3 जुलाई

एडलवाइस म्युचुअल फंड ने 3,000 करोड़ रुपये के निर्गम के लिए शुक्रवार को भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण शुरू किया। इसे 11,000 करोड़ रुपये तक के आवेदन को बनाए रखने के विकल्प के साथ पेश किया गया है।

फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड प्रबंधक के तौर पर एडलवाइस और सरकार के सलाहकार के तौर पर एके कैपिटल के साथ दूसरे चरण को शुरू किए जाने की घोषणा की थी।

पहला चरण पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था और तब 12,400 करोड़ रुपये जुटाए। 7,000 करोड़ रुपये के एनएफओ को भी 1.8 गुना का आवेदन मिले



थे। इसकी परिपक्वताएं वर्ष 2023 और 2030 से संबंधित थीं।

दो नई भारत बॉन्ड ईटीएफ शृंखलाओं की परिपक्वता अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 होगी। एनएफओ 14 जुलाई से शुरू और 17 जुलाई को समाप्त होगा।

एडलवाइस म्युचुअल फंड ने 2025 की परिपक्वता वाली योजना में 6,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 2,000 करोड़ रुपये

और 2031 की परिपक्वता में 5,000 करोड रुपये के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ करीब 1,000 करोड रुपये

जुटाने की योजना बनाई है। ईटीएफ निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स की कंपनियों में निवेश करेगा जिनमें एएए रेटिंग वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। म्युचुअल फंड उन लोगों के लिए समान परिपक्वताओं के साथ फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) भी शुरू

रुपये के भारत बॉन्ड ईटीएफ के दूसरे चरण में 11,000 करोड़ रुपये तक के आवेदन को बनाए रखने का विकल्प है

■मूल रूप से 3,000 करोड़

∎एनएफओ १४ जुलाई से शुरू और 17 जुलाई को समाप्त

करेगा, जिनके पास डीमैट खाते

एडलवाइस ने एक बयान में कहा कि इसमें 25 फीसदी हिस्सा छोटे निवेशकों के लिए और आरक्षित होगा और 75 फीसदी सेवानिवृत कोषों. क्युआईबी और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए होगा।

ईटीएफ पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ईटीएफ

विकल्प से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को करीब 34.000 करोड रुपये की अनुमति मिल सकती है, और चालू वित्त वर्ष में ऐसी कई अन्य पेशकशों की संभावना है।

ईटीएफ पहली पेशकश के शरू होने के बाद से निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और दो परिपक्वताओं ने सालाना आधार पर करीब 12.35 फीसदी और 12.77 फीसदी प्रतिफल दिया। पहले 100 दिन में से 84 में दो पत्रों ने बढत के साथ कारोबार किया। प्रत्येक परिपक्वता के लिए औसत कारोबार मात्रा लगभग ४ करोड रुपये रही।

फिलिप कैपिटल में निर्धारित आय खंड के कंसल्टेंट जयदीप सेन के अनुसार, मौजूदा ईटीएफ में, परिपक्वता 2023 में है जो तीन साल से कम की है, जिसने इसे दीर्घावधि पंजीगत लाभ कराधान या सचकांक लाभ के अयोग्य बना दिया है। लेकिन नई परिपक्वताओं को ये लाभ मिलेंगे। सेन का कहना है कि खर्च अनुपात शून्य होने से भी ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा।

## पहली छमाही में इक्विटी फंड जुटाने की गतिविधियां बढ़ीं

सुंदर सेतुरामन और ऐश्ली कुटिन्हो मुंबई, 3 जुलाई

साल की पहली छमाही में इक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में 50 फीसदी की उछाल देखने को मिली, जिसकी अगुआई बडी कंपनियों मसलन रिलायंस इंडस्टीज, हिंदस्तान यनिलीवर आदि के बडे लेनदेन ने की। हालांकि इक्विटी पुंजी बाजार में शुल्क का संग्रह सात फीसदी घटा क्योंकि निवेश बैंकों ने बड़े इश्यू का कामकाज हाथ में लेने के लिए शुल्क का बलिदान दिया।

जनवरी-जून 2020 के दौरान इक्विटी पूंजी बाजार का अंडरराइटिंग शुल्क 9.6 करोड़ डॉलर रहा, जो साल 2019 की समान अवधि के मकाबले 6.7 फीसदी कम है। वित्तीय सुचना प्रदाता रेफ्निटव ने यह जानकारी दी। इक्विटी पूंजी बाजार में 52 फीसदी ज्यादा रकम जुटाई गई और यह 20 अरब डॉलर के पार निकल गई, साथ ही यह साल 2019 की पूरी अवधि के करीब-करीब बराबर है।

इंक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, पात्र संस्थागत नियोजन कार्यक्रम और ब्लॉक डील आदि शामिल होते हैं। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क में कमी की वजह इक्विटी पूंजी बाजार की कुल गतिविधियों में आईपीओ की कम हिस्सेदारी है। इस साल अब तक सिर्फ एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ ही बाजार में उतरा है। इक्विटी पूंजी बाजार की गतिविधियों में मोटे तौर पर ब्लॉक डील के जरिए मजबूती आई।

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, हमने इस साल अनुवर्ती पेशकश मसलन राइट्स इश्यू, क्यूआईपी और ब्लॉक डील की भरमार देखी है। किसी अन्य पेशकश के मुकाबले आईपीओ का शुल्क ज्यादा होता है क्योंकि पहले से सूचीबद्ध कंपनियों की अनुवर्ती पेशकश के मुकाबले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में निवेश बैंकरों को ज्यादा मेहनत करनी होती है और समय भी लगता है। साथ ही बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां शुल्क पर काफी मोलभाव करती हैं। आने वाले समय में शुल्क आय में बढोतरी के लिए आईपीओ बाजार में सधार जरूरी है।

पहली छमाही में इक्विटी बाजार के अहम लेनदेन में आररआईएल का राइट्स इश्यू, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की तरफ से एचयुएल की 3.4 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बिक्री, भारती एयरटेल का 2 अरब डॉलर का क्यूआईपी, एसबीआई कार्ड्स का 1.4 अरब डॉलर का आईपीओ और प्रवर्तक भारती टेलिक़म की तरफ से भारती एयरटेल की 1.15 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बिक्री शामिल है। पूंजी बाजार के स्वतंत्र प्रोफेशनल प्रांजल श्रीवास्तव ने कहा, इस साल की गतिविधियों में ब्लॉक डील की भरमार है। क्यूआईपी और आईपीओ के मुकाबले ब्लॉक डील का शुल्क काफी कम होता है। यह सिर्फ प्लेसमेंट ट्रांजेक्शन है और यहां आपको विपणन पर महज 50 आधार अंक मिलेंगे। इसमें कोशिश सिर्फ विपणन की होती है और कोई अन्य दस्तावेजीकरण या सेबी की प्रक्रिया शामिल नहीं होती। क्युआईपी में आपको दस्तावेज बनाने होते हैं और उसे स्टॉक एक्सचेंज ले जाना होता है। आने वाले समय में कछ और राइटस इश्यू हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा शुल्क शायद ही मिलेगा जब तक कि उसमें अंडरराइटिंग

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि पहली छमाही में हुए सौदे को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अवधारणा में हुए सुधार से मजबूती मिली। मार्च में रिकॉर्ड बिकवाली के बाद जन तिमाही में विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने जोर पकडा।

#### POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LIMITED

(CIN: L28129MH1971PLC015207)

Registered Office: 771, Century Bhayan, 1st Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030, Maharashtra Tel: +91 022-24304198 / 24307437.

E-mail: upalbby@gmail.com; investors uppl@yahoo.com Website: www.universalprime.in Contact Person: Ms. Priyanka Motwani, (Company Secretary/ Compliance Officer)

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer PA") is being issued by Mr. Prakash Kumar Mohta (hereinafter referred t as the "Acquirer") to the Public Shareholders of Universal Prime Aluminium Limited (hereinafter referred to as the "Company" in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of face value of Rs. 10/- each ("Equity Shares") of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the "BSE"/ "Stock Exchange") pursuant Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") ("Delisting Offer"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 27, 2019 ("Public Announcement"/ "PA") and the Letter of Offer ("LOF") dated November 27, 2019. The capitalized terms used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.

The Acquirer had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF 41, 43,665 Equity Shares representing 52.01% of paid-up equity share capital of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders holding Equity Shares were invited to submit consent letter and transfer of shares to Acquirer, in accordance with the Delisting Regulations

The Acquirer proposes to acquire the entire equity shares of the Company from the Public Shareholders indicating ar exit price of Rs. 3.50/- per Equity Share specifically dispensing with the exit price discovery through book building method in terms of Regulation 27 (4) under chapter VII of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. The Exit Price is justified with particular reference to the applicable parameters mentioned in Regulation 15 SEBI (Delistin of Equity Shares) Regulations, 2009 and specifically the consent for dispensing with the exit price discovery through book building method has been communicated to the public shareholders.

Success of the Delisting Offer

In terms of Regulation 27 (3)(d) under chapter VII of the Delisting Regulations, and as stated in clause 8.1 of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 37,29,299 Equity Shares (90% of the public shareholding) give their consent in writing to the proposal for delisting, and have consented either to sell their equity shares at the price offered by the Acquirer/promoter or to remain holders of the equity share:

b) The acquirer has received consent for delisting for 3822095 shares i.e. equal to 92.24% of the public holding which is more than required for delisting offer to be successful. The acquirer shall acquire 593759 shares which were validly tendered at the exit price. The balance 3228336 equity share representing 40.52% of total paid-up capital of the Company held by various shareholders have agreed to continue as shareholder of the Company and they may also be considered as Promoter of the Company. After completion of such acquisition the shareholdin the promoters shall be shall be 95.964% of the paid up equity share capital of the Company.

In terms of Delisting Regulations, and as per Regulation 27 (3) (c) the Public Shareholders holding Equity Shares were required to give their consent in writing for the Delisting offer, provided that if the Acquirer along with the Share Transfer Agent to the Offer demonstrate that he has delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "LOF Delivery Requirement"). Further pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) 27 (3) (c) of the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirer or the Share Transfer Agent to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.

Maheshwari Datamatics Private Limited., Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on 29th November 2019 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., November 27, 2019 through Registered Post/ Speed Post / Email (where email ids were available). The Registrar has confirmed that the LOF has been dispatched to all the Public Shareholders by Registered Post/Speed Post / Email (where email ids were available) and the Acquirer is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of LOF.

The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations

All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price will be paid consideration at the Exit Price of Rs. 3.50/- (Rupees Three Fifty Paise Only). The last date of payment of consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price originally scheduled on or before Wednesday, April 15, 2020, which the Acquirer could not complete as there was country wide lock down & Acquirer could access their office only after 8th June, 2020.

Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the Equity Shares of the Company from the BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this Post Offer

Outstanding Equity Shares after Delisting

In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares will be able to offer their Equity shares to the to the Promoter Acquirer at the Exit Price Rs. 3.50/- per equity share for the period of one year starting from the date of delisting of the Equity Shares from the BSE Ltd ("Date of Delisting") i.e. ("Exit Period"). In the events of any public shareholder not receiving, or misplacing their Exit offer Letter, they may obtain a copy by writing to the Company of the Registrar and share transfer agent of the Company.

All other terms and conditions set forth in the PA and LOF remain unchanged.

This Post Offer PA is issued by the Acquirer in terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations. If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer, they may contact the Company or the Registrar to the

> REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER Maheshwari Datamatics Private Limited CIN: U20221WB1982PTC034886

23, R. N. Mukherjee Road 5th Floor, Kolkata-700 001 Tel. No.: +91 33 2248 2248 E-Mail ID: mdpldc@yahoo.com Contact Person: Mr. S. Raigopal Website: www.mdpl.in SEBI Reg. No.: INR000000353

Note: The Acquirer could not make the newspaper advertisement on 27th March, 2020 in terms of Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations") ("Delisting Offer") as there was Country wide lockdown due to impact of CoVID - 19 pandemic from 22nd March, 2020, the Acquirer could not access their office till 08th June, 2020. Hence various events to be taken by the Acquirer/Promoter got delayed, which was major force, i.e. reason beyond the control of Acquirer/Promoter as the entire country was in lock down mode, there were restrictions on the physical movement of every individual in the country.

Place: Kolkata For and Behalf of the Acquire Date: 03-07-2020 Prakash Kumar Mohta

## बीएसएनएल की उधारी सीमा में हुआ इजाफा

## वित्त वर्ष 21 के लिए कंपनी की योजना

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 3 जुलाई

**भारत संचार** निगम को राहत मिली है क्योंकि सरकार को इस कंपनी की उधारी सीमा 31,213 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,713 करोड़ रुपये करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021 में कुछ शर्तों के साथ सॉवरिन गारंटी बॉन्ड के जरिए 8,500 करोड़ रुपये जुटाया जाना शामिल है। यह मंजूरी बीएसएनएल के कायापलट के लिए अहम है, जिसमें 4 जी नेटवर्क की स्थापना शामिल है ताकि वह निजी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस साल फरवरी तक भारतीय मोबाइल बाजार में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 10.32 फीसदी थी।

हालांकि यह सख्त शर्तों के साथ

आया है। बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2021 और भविष्य के लिए अपना परिचालन राजस्व सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाना होगा ताकि वह आंतरिक संग्रह से पूंजीगत खर्च समेत सभी खर्च पूरी कर सके और समय पर कर्ज का पुनर्भुगतान भी कर सके। दूसरा, उसे वित्त वर्ष 2021 के लिए अनिवार्यता का प्रमाणपत्र दूरसंचार विभाग को देना होगा कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कर्ज का प्रस्ताव वित्तीय रूप से उपयुक्त है। तीसरा, उसका कुल बकाया कर्ज तय सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसे अपना परिचालन खर्च कम रखना होगा। साथ ही बीएनसएनएल को अपनी इकाइयों को उचित निर्देश जारी करना होगा कि पूंजीगत व परिचालन खर्च के लिए खर्च की सही बुकिंग की गई है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को हाल में झटका लगा जब वह करीब 8,000 करोड़ रुपये के 4जी उपकरण की निविदा को रद्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह देसी दुरसंचार कंपनियों के विरोध में हुआ, जिसने कहा कि उनके साथ विभेद दिया गया है और यह सरकार की स्थानीय खरीद नीति के खिलाफ है। अब दुरसंचार विभाग ने तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में मुसीबत भरा हो सकता है।

### रकम का आगमन

- 8.500 करोड रु. सॉवरिन गारंटी बॉन्ड से
- **10,811** करोड़ रु. बैंक
- **1,000** करोड़ रु. मुद्रीकरण से
- **17.175** करोड रु.परिचालन

### मुख्य खर्च

- ■वेतन पर 6,740 करोड़ रु.
- परिचालन खर्च 2,463 करोड़ रू.
- वित्त वर्ष 20 की परिचालन खर्च देनदारी 3.676 करोड रु.
- कर्ज पर ब्याज **2.255** करोड़ रू.
- कर्ज का पुनर्भुगतान **6,800** करोड़ रू.
- पूंजीगत खर्च 3,758 करोड़ रू.

आठ सदस्यों की समिति बनाई है. जो बीएसएनएल के विवादास्पद 4जी निविदा के लिए तकनीकी विशेषता पर सिफारिश देगी।

यहां तक कि निविदा पर नीति आयोग ने दरसंचार विभाग और बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की और दूरसंचार कंपनियों टेक महिंद्रा, ट्यूलिप सॉफ्टवेयर व सी-डॉट के साथ भी। थिंक टैंक ने बीएसएनएल से कहा है कि वह अपने 4जी नेटवर्क के लिए देसी समाधान पर ध्यान दे। हालांकि बीएसएनएल के चेयरमैन पी के पुरवार ने स्पष्ट किया है कि देसी कंपनियों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह साफ हो गया है कि उत्पादों को और विकसित करने की दरकार है। साथ ही उनकी कंपनी के पास प्रयोग के लिए रकम नहीं है, ऐसे में निविदा को अंतिम रूप देने से पहले क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए। अगर यह कदम उठाया गया है तो संशोधित निविदा वैश्विक विनिर्माताओं मसलन चीन की हुआवे व जेडटीई और यूरोपीय दिग्गज एरिक्सन व नोकिया के लिए

### ☐ HDFC

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन : L70100MH1977PLC019916)

पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैंकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020 दूरभाष नं. : 022 6176 6000 वेबसाइट : www.hdfc.com ई-मेल : investorcare@hdfc.com कॉर्पोरेट कार्यालय: एचडीएफसी हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 165-166, बैकबे रीक्लेमेशन,

चर्चगेट, मुम्बई-400 020, दूरभाष नं. : 022 6631 6000 निवेशक सेवा विभाग : 5वीं मंजिल, रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020, दूरभाष नं. : 022 6141 3900

43वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कॉर्पोरेशन'') के सदस्यों की 43वीं वार्षिक बैठक (एजीएम) कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 क् क्रमशः सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 (''एमसीए परिपत्र'') के अनुपालन में सूचना एजीएम प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 19 जून, 2020 में वर्णित के अनुसार प्रकार्यों के लेन-देन हेतु द्विमार्गी वीडियो कांफ्रेंस सुविधा ('वीसी') के माध्यम से बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 को 2:30 बजे अप. को आयोजित की जानी निर्धारित है। यदि स्थानीय प्राधिकरण अनुमति देते हैं तो भौतिक बैठक भी रामा सुन्दरी वाटुमुल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020 पर आयोजित की जायेगी। यदि निगम भौतिक एजीएम आयोजित करने में समर्थ नहीं होता है तो इसकी सचना सदस्यों को देने हेतु आदेश में आवश्यक सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी और ऐसी स्थिति में एजीएम में भागीदारी एमसीए परिपत्रों के अनुसार केवल वीसी माध्यम से ही की जायेगी।

पुनः एमसीए परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा निर्गत परिपत्र सं . SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 के अनुपालन में कॉर्पोरेशन ने एजीएम प्रारम्भ करने की सचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों के पास भेजी है जिनके ई-मेल पते कॉर्पोरेशन या सम्बद्ध डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट (डी.पी.) के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज www.hdfc.com, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम आयोजित करने की सूचना www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है पुनः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम तथा कॉर्पोरेशन की शेयर अन्तरण पुस्तिक एजीएम के उद्देश्य हेतु एवं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन वित्त वर्ष 2019–20 हेतु रु. 2 प्रत्येक के रु. 21 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश प्राप्त करने के पात्र सदस्यों का निर्धारण करने हेतु सोमवार् दिनांक 13 जुलाई, 2020 से बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तथा जिन्होंने सीधे खाते में लाभांश राशि की इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति के लिए अपने बैंक खाते का विवरण अब तक पंजीकत/अपडेट न कराने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे इसे सेबी द्वारा अपेक्षित के अनसार अपेक्षित दस्तावेज जमा करके कॉर्पोरेशन के साथ इसका पंजीकरण करा लें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने बैंक खातों का विवरण अपने सम्बद्ध डीपी से पंजीकृत/अपडेट करा लें।

पुनः एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कथित सुचना में सुचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने हेतु कॉर्पोरेशन अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और उसने वीसी तथा ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ग्रहण की हैं।

ાર	रिमाट इ-वाटिंग तथा वासा सुविधा सं सम्बान्धत कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण निम्नालाखत ह :				
	रिमोट ई-वोटिंग तथा वीसी हेतु लिंक	www.evoting.nsdl.com			
	ईवेन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	112957			
		बृहस्पतिवार, 23 जुलाई, 2020			
	पात्र सदस्यों के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि				
	रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारम्भ	सोमवार, 27 जुलाई, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा.			
		बुधवार, 29 जुलाई, 2020 को 5.00 बजे अप.। इसके पश्चात एनएसडीएल			
		द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल निष्क्रिय कर दिया जायेगा।			

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सचना भेजे जाने के पश्चात कॉर्पोरेशन का सदस्य होता है तथा कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता या जिसने कॉर्पोरेशन/डीपी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तु, यदि ऐसा सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान हेतु अपने वर्तमान यूजर अईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

ई-वोटिंग सविधा उन सदस्यों को जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, उन्हें अपना मतदान करने हेत एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में शामिल तो हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु विस्तृत निर्देश तथा ई-वोटिंग की रीति एजीएम आयोजित करने की सूचना में

वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होने या ई–वोटिंग प्रणाली से अपना मतदान करने से सम्बन्धित किसी कठिनाई या पूछताह के मामले में सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं :

हेतु	नाम	ई-मेल	सम्पर्क नम्बर
ई-वोटिंग	श्री अमित विशाल	amitv@nsdl.co.in	022-2499 4360
	सुश्री पल्लवी म्हात्रे	pallavid@nsdl.co.in	022-2499 4545
	एनएसडीएल	evoting@nsdl.co.in	1800-222-990
वीडियो कांफ्रेंस	श्री अनुभव सक्सेना	anubhavs@nsdl.co.in	022-2499 4835

कृते हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अजय अग्रवाल कम्पनी सचिव स्थान : मुम्बई तिथि : 3 जुलाई, 2020 एफसीएस : 9023